Newspaper Clips

May 12, 2012

Financial Express, ND 12/05/2012 P-22

IIT Council to discuss common engineering entrance exam

Kiritika Suneja
New Delhi, May 11

WITH THE government planning to scrap the 50-year-old IIT-JEE exam, the Indian Institutes of Technology (IIT) Council will have a crucial meeting on Saturday to decide the fate of the exam and find an alternative. The meeting is also a build-up to the country's highest education advisory body, Central Advisory Board of Education (CABE), which is set to meet next month.

The meeting assumes significance as the ministry of human resource development's (MHRD) proposal of a common national entrance exam for students aspiring to join central engineering institutions has been in-principle approved by states. If implemented, the exam will reduce the burden of multiplicity of exams on students.

The aptitude-cum-advanced knowledge test will be in place in 2013 once the IIT Joint Entrance Examination (JEE) and the All-India Engineering Entrance Examination (AIEEE) are merged.

"We are yet to discuss the issue and the decision will happen after a consensus," said an IIT director who is coming to attend the meeting in Delhi. Incidentally, the IITs and National Institutes of Technology (NITs) are opposing the scrapping of the JEE on grounds of dilution of quality. Also, the CABE committee meeting has been postponed by almost a month as the government and stakeholders could not find common ground for the national level exam.

While the IITs and other central educational institutions are proposing to adopt a weightage of 40% for state board marks, test scores will have 60% weightage.

However, states can adopt their own weightages for state board marks and the national examinations for admission to state-level institutions. The academic component of the main and advanced examinations would be handled by IITs whereas the management and conduct of the examination would be done by CBSE in collaboration with state boards.

Hindustan ND 12/05/2012 p-5

आईआईटी के सीनेट ने सौंपी मंत्रालय को रिपोर्ट

आईआईटी-जेईई से ही होगा 2013 में दाखिला

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

आईआईटी तथा अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव अगले साल से लागू होने के आसार नहीं हैं। पुराने आईआईटी ने कॉमन प्रवेश परीक्षा संबंधी मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

पुराने आईआईटी ने सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वे 2013 में भी आईआईटी-जेईई परीक्षा के माध्यम से ही दाखिला देंगे। पुराने आईआईटी का कहना है कि अगर 2014 से कॉमन एंट्रेंस प्रणाली लागू करनी है तो उस पर फैसला अभी नहीं बल्कि अगले साल किया जाये। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सीनेट ने शुक्रवार अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेज दी। अब शनिवार को सिब्बल की अध्यक्षता में आईआईटी परिषद की बैठक होगी जिसमें कॉमन एंट्रेंस प्रणाली के भविष्य का फैसला होगा।

फिलहाल आईआईटी में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी आईआईटी-जेईई होती है जबकि इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी एआईईईई आयोजित होती है। सिब्बल इन दो अलग-अलग परीक्षाओं की जगह एक ही परीक्षा चाहते हैं।

गौरतलब है कि हाल में सिब्बल ने आईआईटी परिषद की बैठक में यह मुद्दा रखा था जिसका विरोध हुआ था। सिब्बल ने आईआईटी से कहा था कि अगर वह चाहें तो नयी प्रणाली को अपनायें, उनके साथ किसी भी तरह की जोर जबर्दस्ती नहीं होगी। इस बीच मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि अगर 2013 में कॉमन एंट्रेंस शुरू नहीं हो पाता है तो फिर इसके लागू होने के आसार और कम हो जायेंगे।

सिब्बल की मंशा

सिब्बल चाहते हैं कि सभी आईआईटी तथा केंद्र सरकार के अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 2013 से ही कॉमन एंट्रेंस की प्रणाली अपनायी जाये जिसमें 12वीं कक्षा के अंकों को भी वरीयता दी जाये। लेकिन आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, बाम्बे, गुवाहाटी और मद्रास ने इसे लेकर सवाल उठाये है।

HRD MINISTRY TO HOLD MEET OF ALL IITs TODAY

Vanita Srivastava
Vanita.shrivastava@hindustantimes.com

NEW DELHI: Even as the students are confused on the pattern for the 2013 IIT-JEE exam , the HRD ministry will have wide ranging deliberations with different IIT directors and chairmen on the recommendations of different senates at the IIT Council meet in Delhi IIT on May 12.

While a broad consensus could emerge after the meeting, the final announcement will perhaps be made after the meeting of the Central Advisory Board of Education on June 6. The mood of different senates is not in favour of the government proposal.

All the IITs, except IIT Roorkee, have opposed any change in pattern from 2013. But IIT Roorkee is also not supporting the proposal of the government that there should be a common engineering exam for selection.

It favours a two-tier exam, where the common engineering test could be used simply as a filtering exam.

IIT Guwahati has supported the government's proposal to select students on the basis of a common engineering exam, but it has some reservations on a smooth implementation from 2013.

IIT Kharagpur feels there should be a lean period of 2-3 years before any actual experimentation.

It is also not in favour of the government's proposal in the current form.

IIT Chennai, IIT Kanpur and IIT Delhi feel the common exam could be used just for screening candidates for the JEE exam.

Dainik Jagran ND 12/05/2012
P-7

हंगामे के बीच सिब्बल ने पारित कराए दो विधेयक

नई दिल्ली, एजेंसी : एनसीईआरटी की किताब में डा. बीआर अंबेडकर के आपत्तिजनक कार्टून पर घिरे सिब्बल ने शुक्रवार को जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा में शैक्षिक सुधारों की राह खोलने वाले दो विधेयक पारित करा लिए। इन विधेयकों के पारित होने से कई तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल सकेगा। इन विधेयकों के पारित होने से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च के छात्र को वैधानिक डिग्रियां मिल सकेंगी। साथ ही आठ नए संस्थानों को आइआइटी का दर्जा मिल सकेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी(संशोधन) विधेयक 2011 को राज्यसभा पहले ही पारित कर चुकी है जिसके तहत विभिन्न राज्यों में आठ नई आइआइटी खोली जा सकेंगी। इसके जरिये इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एकीकृत कर विधेयक के अधीन लाया जाएगा।संशोधित विधेयक के अनुसार इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा। एक अन्य विधेयक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी (संशोधित) 2010 को भी राज्यसभा के बाद लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इसके तहत कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिलेगा।

Dainik Bhasker, ND 12/05/2012
P-15

आईआईटी-आईआईएम में ओबीसी छात्र बढ़े

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की तादाद में वर्ष 2010-11 में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि वर्ष 2010-11 में आईआईएम में अन्य पिछड़ा वर्ग के 23.05 फीसदी छात्रों ने प्रवेश लिया, जबकि वर्ष 2009-10 में यह 14.52 फीसदी थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 में आईआईटी में अन्य पिछड़ा वर्ग के 23.61 फीसदी छात्रों ने प्रवेश लिया। वर्ष 2009-10 में उनका प्रतिशत 20.38 था। इसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2010-11 में ओबीसी के 19.09 फीसदी छात्रों ने और वर्ष 2009-10 में ओबीसी के 13.52 फीसदी छात्रों ने प्रवेश लिया।

Hindustan Times, ND 12/05/2012
P-10

Lt Gen Zameeruddin Shah appointed AMU V-C

ALIGARH: President Pratibha Patil has appointed Lt Gen (retired) Zameeruddin Shah as the new vice-chancellor of the Aligarh Muslim University. The HRD ministry confirmed his appointment on Friday. Lt Gen Shah will hold the post for a period of five years or till 70 years of age. He told the university spokesperson that he will assume duty as the vice-chancellor at the earliest.